बहुजन हिताय!

सक्षम भारत

बहुजन सुखाय!

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 155 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 03 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

डीपफेक पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती, अनिरुद्धाचार्य से जुड़े एआई कंटेंट के प्रसार पर लगाई अंतरिम रोक

नई दिल्ली। धार्मिक उपदेशक अनिरुद्धाचार्य के पक्ष में एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर एआई सृजित डीपफेक और मीम-आधारित सामग्री के अनधिकृत रोक लगा दी है। अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए आध्यात्मिक गुरु का मामला पहली नजर में काफी मजबूत प्रतीत होता है। उनकी लोकप्रिय और सर्वमान्य छवि को देखते हुए अगर अंतरिम आदेश नहीं पारित किया गया तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी और इसकी मौद्रिक रूप से नहीं की जा सकेगी। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर पेश की गई सामग्री व्यंग के बजाय अपमानजनक प्रतीत होती है और अनिरुद्धाचार्य के व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन करती है।

विकसित भारत लक्ष्य के लिए सार्वजनिक सेवाओं को लगातार अद्यतन करने की जरूरत- प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बदलते समय के साथ सिविल सेवाओं को लगातार अद्यतन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने साधना सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत पर एक वीडियो संदेश में कहा कि देश के शासन को नागरिकों के लिए दैनिक आधार पर जीवनयापन की सुगमता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। मोदी ने कहा कि देश में शासन का सिद्धांत नागरिक देवो भव के मंत्र पर आधारित है। उन्होंने कहा कि सामूहिक भावना के साथ यह मंत्र सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सक्षम और नागरिकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने का लक्ष्य रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब हम प्रशासनिक सेवाओं में सुधार और बदलाव की बात करते हैं तो उसका एक आशय है कि लोक सेवकों के व्यवहार में बदलाव। हम सभी जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था में जोर अधिकार होने पर यादा होता था लेकिन आज देश का जोर कर्तव्य भावना पर यादा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रयासों को 2047 के विकसित भारत के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, देश

के विकास पथ पर हमारे (सिविल सेवकों) द्वारा किए जा रहे कार्यों का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे एक निर्णय से कितने नागरिकों का जीवन बदल सकता है हमारा व्यक्तिगत परिवर्तन संस्थागत परिवर्तन कैसे बन सकता है यह प्रश्न हमारे हर प्रयास का हिस्सा होना चाहिए। मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी को समझना और उसका सही उपयोग करना सार्वजनिक सेवा का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, आप तभी बेहतर प्रशासक और बेहतर लोक सेवक बन सकते हैं जब आप प्रौद्योगिकी और डेटा को समझें।

यही आपके निर्णय लेने का आधार बनेगा, इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और निरंतर सीखने को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। साधना (राष्ट्रीय उन्नति के लिए अनुकूल विकास और मानवीय योग्यता को मजबूत करना) सप्ताह का आयोजन क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) द्वारा दो से आठ अप्रैल तक किया जा रहा है। यह सप्ताह भारत के सिविल सेवा तंत्र में सबसे बड़े सहयोगी क्षमता निर्माण प्रयासों में से एक है। यह आयोग शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, नागरिक-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार बनाने हेतु रूपरेखा तैयार करता है, मानक निर्धारित करता है और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। यह क्षमता विकास और योग्यता पर आधारित शिक्षा के माध्यम से सिविल सेवा सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी रूपरेखा का संरक्षक है।

हनुमान जन्मोत्सव पर दिल्ली के मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़, करोल बाग मंदिर पहुंची सीएम रेखा

नई दिल्ली । भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध हनुमान जी साहस और निष्ठा के साक्षात प्रतीक माने जाते हैं। आज दो अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल इस दिन पर ही हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गुरुवार को हनुमान जयंती के अवसर पर राजधानी दिल्ली के मंदिरों में भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचने लगे थे। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर श्री मरघट वाले हनुमान बाबा मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। यहां भक्तों ने भगवान हनुमान को सिंदूर और प्रसाद चढ़ाया। वहीं पांडव कालीन कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरती में भाग लिया। मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हनुमान जयंती का पर्व पूरे उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। कई स्थानों पर भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर करोल बाग स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रभु श्रीराम के परम भक्त हनुमान जी से राजधानी के हर परिवार में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने हनुमान जी की अखंड भक्ति, निस्वार्थ सेवा और पराक्रम को सनातन मूल्यों का सर्वोच्च आदर्श बताते हुए सभी के जीवन में साहस, संयम और समर्पण का संचार होने की प्रार्थना की। हनुमान जी के गुरु के बारे में जब भी बात होती है तो सूर्यदेव को उनका गुरु कहा जाता है। यह बात आंशिक रूप से सही भी है क्योंकि सूर्य देव ने ही उन्हें शिक्षा और ज्ञान प्रदान की थी। लेकिन हनुमान चालीसा में इस बात का उल्लेख मिलता है कि वह माता सीता को अपना गुरु मानते थे। हनुमान चालीसा की शुरुआत दो दोहों से होती है, जिसमें पहला शब्द श्री गुरु चरन सरोज रज है। कई विद्वानों के अनुसार यहाँ श्री गुरु का तात्पर्य माता सीता से है।

केजरीवाल का गुजरात सरकार पर बड़ा आरोप, बोले- आप कार्यकर्ताओं पर हो रही सुनियोजित कार्यवाही

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सुनियोजित कार्रवाई किये जाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पटेल के साथ बैठक का अनुरोध किया। केजरीवाल ने पत्र में गुजरात में पिछले तीन महीनों में दर्ज 145 प्राथमिकी और 160 से अधिक गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने लिखा, लोगों को 'आप' के रूप में पहली बार एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प मिला है। लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पढ़े-लिखे, बेखौफ, ईमानदार और देशभक्त व्यक्तियों की पार्टी है, जो भाजपा से कभी समझौता नहीं करेगी। केजरीवाल ने कहा, यही कारण है कि हाल के वर्षों में गुजरात में 'आप' की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है और अब बड़े पैमाने पर चर्चा है कि राज्य में भाजपा सत्ता से बाहर होने वाली है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। उन्होंने भाजपा पर 'आप' के ज्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके पार्टी को कमजोर करने तथा उसका अस्तित्व मिटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया।

'आप' प्रमुख ने कहा, इस साजिश के तहत भाजपा सरकार के आदेश पर अकेले पिछले तीन महीनों में गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 145 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 160 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में राज्य में 'आप' के 10,000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की योजना है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी 'आप' नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों का दौरा कर रहे हैं तथा उन्हें गुजरात न छोड़ने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं।

सीएम रेखा ने कोरोना योद्धाओं को दी श्रद्धांजलि, परिवारों को मिली 1 करोड़ की आर्थिक सहायता

नई दिल्ली ।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोरोना काल में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवारों से मुलाकात कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री ने छह परिवारों को वर्षों से लंबित एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की और आश्वस्त किया कि सरकार सम्मान, संवेदना और संकल्प के साथ हर परिस्थिति में उनके साथ दृढ़ता से खड़ी है. इस अवसर पर दिल्ली पुलिस ट्रैफिक यूनिट के एएसआई राधे श्याम के परिजनों को भी 1 करोड़ की सहायता राशि दी गई, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहायता उस अपूरणीय क्षति की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन यह सरकार के उस अटूट संकल्प का

प्रतीक है कि इन कर्मयोगियों का बलिदान सदैव स्मरण में रहेगा और दिल्ली उनके प्रति हमेशा खड़ी रहेगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन परिवारों को अतीत में हुई मुश्किलों, खासकर पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई देरी का भी संज्ञान लिया. कई लोगों को प्रक्रियागत देरी और मुआवजे के देर से मिलने के कारण लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा था.उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब ऐसे मामलों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि किसी भी पात्र परिवार को सहायता मिलने में अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े. उनके शब्दों से वहां मौजूद लोगों को साफ तौर पर राहत और तसल्ली मिली. ये छह लाभार्थी MCD, DTC, दिल्ली जल बोर्ड, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, NDMC और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जैसे विभिन्न सरकारी निकायों से जुड़े थे. पैरामेडिकल स्टाफ ने अस्पतालों और टेस्टिंग सेंटरों में काम करते हुए अपनी जान जोखिम में डाली, जबकि अन्य विभागों के कर्मचारियों ने लॉकडाउन के दौरान पानी की सप्लाई, सफाई और ट्रांसपोर्ट जैसी जरूरी सेवाओं की बिना किसी रुकावट के डिलीवरी सुनिश्चित की.

बड़ा सवाल- दिल्ली में बसों की संख्या में इजाफा, फिर भी 10 लाख मुसाफिर गायब; कोविड महामारी के बाद से आई गिरावट

नई दिल्ली । दिल्ली में बसों पर सरकार का खर्च लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यात्रियों की संख्या उसी अनुपात में नहीं बढ़ रही। उल्टा, कोविड के बाद से बसों में सफर करने वालों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद बस सेवा लोगों की पहली पसंद क्यों नहीं बन पा रही। कोविड से पहले राजधानी में डीटीसी और क्लस्टर बसों में रोजाना औसतन करीब 40 से 45 लाख यात्री सफर करते थे। यह संख्या दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की ताकत मानी जाती थी। लेकिन अब यह घटकर लगभग 30 से 35 लाख के बीच सिमट गई है। यानी हर दिन करीब 8 से 10 लाख यात्री बसों से गायब हो चुके हैं। दिल्ली के आर्थिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सबसे यादा 11,964 करोड़ का बजट दिया गया है। इसके अलावा डीटीसी के घाटे को पूरा करने के लिए अलग से हजारों करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। लेकिन इन भारी निवेशों के बावजूद बसों में यात्रियों की संख्या का स्थिर या कम रहना यह संकेत देता है कि समस्या कहीं गहरी है। ग्राउंड पर स्थिति बताती है कि कई रूट्स पर बसों की फ्रीक्वेंसी कम है, टाइमिंग अनिश्चित है और लास्टमाइल कनेक्टिविटी कमजोर बनी हुई है। दिल्ली में बसों के बेड़े (फ्लीट) का विस्तार और इलेक्ट्रिक बसों की एंट्री इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बनाती है। कोविड से पहले 2018-19 में डीटीसी और क्लस्टर मिलाकर कुल बसों की संख्या करीब 5,500 से 6,000 के बीच थी। इसके बाद सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों पर जोर देते हुए बेड़े को बढ़ाना शुरू किया।

दिल्ली में गैस की कालाबाजारी पर सख्ती, 45 सिलिंडर के साथ रिफिलिंग मशीन जब्त; तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में गैस संकट के बीच कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। पालम गांव पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने एलपीजी गैस के अवैध भंडारण और रिफिलिंग करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 45 भारत गैस सिलिंडर के साथ एक टेम्पो बरामद किया गया। अवैध गैस रिफिलिंग और ट्रांसफर करने वाले उपकरण भी जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अनार सिंह, सत्यवीर और विकास कुमार के रूप में हुई है। वहीं

दूसरी दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली के डाबड़ी में अवैध एलपीजी सिलिंडर स्टोरेज और रिफिलिंग रैकेट का खुलासा कर 17 सिलिंडर बरामद किए हैं। अपराध शाखा ने दुकानदार मोहन लाल गर्ग को पकड़ा है। बाद में जांच के लिए मामला द्वारका जिले की डाबड़ी थाना पुलिस को सौंप दिया गया। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने बताया कि पश्चिमी जिले के सीतापुरी इलाके में एलपीजी सिलिंडरों की जमाखोरी की सूचना पर टीम ने दुकानदार मोहन लाल गर्ग (61) को अवैध रूप से एलपीजी गैस सिलिंडर भरते हुए पाया। वह 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सिलिंडर भर रहा था। उस जगह अलग-अलग कंपनियों के कुल 17 एलपीजी गैस सिलिंडर मिले। खाद्य आपूर्ति अधिकारी हरजीत 7 कौर को तुरंत मौके पर बुलाया।

हाईकोर्ट नाराज- कहा- बच्चों की तस्करी की मंडी बन गई है दिल्ली, सरकार; पुलिस और बाल संरक्षण आयोग को नोटिस

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राजधानी अब बाल तस्करी की मंडी बन गई है। कोर्ट ने रेलवे स्टेशनों और आसपास के इलाकों में खुलेआम हो रही बाल तस्करी पर चिंता जताते हुए रेलवे, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस की ओर से दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली अब बाल तस्करी की मंडी बन गई है। इसकी पुष्टि के लिए याचिका पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो घंटे रेलवे स्टेशनों के आसपास घूम लीजिए। पीठ ने कहा कि बाल तस्करी की समस्या न्यायिक आदेशों के बावजूद कम नहीं हुई है। कोर्ट ने बाल संरक्षण आयोग को आंकड़े उपलब्ध कराने और उचित दिशा-निर्देश देने के लिए सुझाव देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। अदालत ने आदेश में कहा कि कोर्ट ने बार-बार चिंता जताई और निर्देश दिए, लेकिन समस्या अभी भी अनियंत्रित है। कोर्ट ने माना कि रेलवे समेत संबंधित विभागों ने उपाय किए, लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन की कमी के कारण स्थिति नहीं बदली। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने बताया कि 2018 से 2024 के बीच रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेलवे परिसर से 84,000 से अधिक बच्चों को बचाया। एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन से बचाई गई एक लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बजाय तस्करों को सौंप दिया गया, जिसे बाद में फिर से रेस्क्यू करना पड़ा। वहीं, याचिका में यह भी कहा गया कि मंत्रालय ने ऐसे बच्चों की पहचान, बचाव और पुनर्वास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की, लेकिन विभाग इसे गंभीरता से उल्लंघन कर रहे हैं।

जिहादी मानसिकता

गत 29 मार्च को दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार जिहादी अहमद लोन उर्फ राजा कश्मीरी को दबोच लिया। बकौल मीडिया रिपोर्ट, उसकी कुदृष्टि राजधानी के पवित्र कालकाजी मंदिर और कनॉट प्लेस जैसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों पर थी। पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर वह लश्कर के लिए भारतीय मुस्लिम युवाओं की भर्ती का जाल बुन रहा था। यह कोई अकेली हालिया घटना नहीं है। कुछ दिन पहले ही देश के विभिन्न राज्यों में चलाए गए एक बड़े आतंकवाद-रोधी अभियान के तहत सुरक्षा एजेंसियों ने आई.एस. अलकायदा से जुड़े 12 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इनमें बाइक टैक्सी चालक मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ, रेस्तरां कर्मचारी मिर्जा सोहेल बेग और लेजर मार्किंग विशेषज्ञ मोहम्मद दानिश शामिल हैं। लब्बोलुआब यह है कि जिस मानसिकता के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने 8वीं शताब्दी में सनातन भारत पर हमला किया, फिर उसके मानसबंधुओं ने सदियों तक जिहाद किया, इस दौरान हिंदू-बौद्ध बहुल अफगानिस्तान का इस्लामीकरण हो गया, 1947 में देश को इस्लाम के नाम पर विभाजित किया गया और 1980-90 के दौर में कश्मीर को हिंदू-विहीन कर दिया गया, वह जिहादी चिंतन अब भी अपरिवर्तित है, चाहे कोई उच्च-शिक्षित ही क्यों न हो। इन गिरफ्तारियों से पहले पिछले साल नवम्बर में दिल्ली में चलती कार में हुए भीषण विस्फोट, जिसे फिदायीन डा. उमर उन नबी ने अंजाम दिया था, उसमें कई लोगों की जान चली गई थी। उस समय दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद से लगभग 3000 किलो विस्फोटक, हथियारों का जखीरा और बम बनाने के उपकरणों के साथ अल-फलाह अस्पताल के कई जिहादी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था। उसी क्रम में गुजरात पुलिस ने डा. अहमद मोहिउद्दीन सैयद को उसके दो सहयोगियों के साथ पकड़ा था, जो अरंडी के बीजों से घातक राइसिन जहर तैयार कर रहा था, ताकि पानी और भोजन के जरिए बड़े नरसंहार को अंजाम दिया जा सके। यदि कोई इन घटनाओं को केवल 'ताजा हालात' मानकर समझना चाहता है, तो वह सच से आंख चुरा रहा है। वास्तव में, भारतीय उपमहाद्वीप में एक वर्ग आज भी उन्हीं आक्रांताओं-कासिम, गजनवी, गोरी, बाबर, औरंगजेब, अब्दाली को अपना 'नायक' मानता है, जिन्होंने इस भूखंड पर 'काफिर-कुफ्र' की अवधारणा से प्रेरित होकर कत्लेआम किया, मंदिर तोड़े और सांस्कृतिक अस्मिता को रौंदा। इस सोच का एक हिस्सा आज भी 'गजवा-ए-हिंद' जैसे खतरनाक मंसूबे को मजहबी जिम्मेदारी मानता है। यही कारण है कि अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, तब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कई छात्र पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो रहे थे। यहां तक कि जम्मू-कश्मीर की रियासती सेना में कई मुस्लिम टुकड़ियां भी मजहब के नाम पर शत्रुओं से जा मिलीं थीं। यह भी स्थापित तथ्य है कि भारत का विभाजन कराने वाले न तो बाहर से आए थे, न ही उनके सभी राजनीतिक समर्थक बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए। यदि ऐसा होता, तो शायद खंडित भारत में मुस्लिम अलगाववाद-कट्टरवाद धीरे-धीरे समाप्त हो जाता या फिर वे इंडोनेशिया-मलेशिया की तरह स्थानीय सनातन संस्कृति से सहज तालमेल बिठा लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत-हिंदू विरोधी मार्क्स-मैकाले मानसपुत्रों ने 'सेकुलरवाद' के नाम पर इस प्रक्रिया को शुरू ही नहीं होने दिया। नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम समाज के एक वर्ग के लिए 'लोकतंत्र' और 'संविधान' विकास या सुधार न होकर केवल पहचान की राजनीति तक सिमट गया है। आजादी के बाद सितम्बर, 1947 में दिल्ली की घटना इस मानसिकता को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार देती है। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, 'पुलिस द्वारा मुस्लिम घरों और मस्जिदों की तलाशी में बम, हथियार और गोला-बारूद के बड़े भंडार बरामद हुए थे।' यह भीड़ की अचानक हुड़दंग नहीं, बल्कि दिल्ली पर फिर से इस्लामी परचम लहराने की तैयारी थी। तब यह स्थिति और गंभीर इसलिए हो गई, क्योंकि पुलिस बल का एक बड़ा मुस्लिम वर्ग अविश्वसनीय निकला। तब सरकार को दूसरे राज्यों से फौज बुलानी पड़ी। उस समय दिल्ली एक प्रकार के भीषण जिहाद से जूझ रही थी। सरदार पटेल ने जिस दृढ़ता से इस मजहबी उन्माद का सामना किया, वह आज भी उदाहरण है। प्यारेलाल द्वारा लिखित 'महात्मा गांधी - द लास्ट फेज' (खंड 2) के अनुसार, जब पटेल को बताया गया कि एक इमारत से मुस्लिमों द्वारा लगातार गोलीबारी हो रही है और उसे हटाने के लिए पूरी इमारत को बम से उड़ाना पड़ेगा, तो पटेल का जवाब था-'तो फिर किया क्यों नहीं?' यह स्पष्ट संदेश था कि देश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। फिर भी डी.पी. मिश्रा (दो बार मध्य प्रदेश से कांग्रेसी मुख्यमंत्री) के अनुसार, उस नाजुक दौर में सरदार पटेल को पूरा राजनीतिक समर्थन प्राप्त नहीं था। यही विकृति आज भी विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। भारत के सामने चुनौती केवल जिहाद से लड़ने की नहीं, बल्कि उस विचारधारा को समझने और रोकने की है, जो इसे जन्म देती है। आतंकवादी अहमद लोन की गिरफ्तारी एक चेतावनी है और एक अवसर भी। सतर्कता इसलिए कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ और मौका इसलिए कि हम समय रहते जिहादी मानसिकता को पहचान सकें। बीती एक सहस्राब्दी में भारत, सतत जनसांख्यिकीय परिवर्तन (बलपूर्वक सहित) के बीच एक-तिहाई भूखंड खो चुका है। शेष भारत, जहां आज भी उसके हिंदू चरित्र के कारण बहुलतावादी सनातन संस्कृति जीवित है, उसे निरंतर पाश्विक शक्तियों से विभिन्न रूपों में चुनौती मिल रही है। इससे मुकाबला करने हेतु सुरक्षा एजेंसियों को सशक्त बनाना तो जरूरी है ही, साथ ही समाज में जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है।

'राजनीति में अपराधियों का बोलबाला'

देश की संसद और राज्यों की विधानसभाएं देश और विदेश से संबंधित गंभीर विषयों पर चर्चा करने के मंच हैं लेकिन अब लोकसभा और विधानसभाओं में ऐसे सदस्य चुन कर पहुंच रहे हैं जिनकी अपनी पृष्ठभूमि आपराधिक है। 2009 में संसद में पहुंचे 30 प्रतिशत लोकसभा सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले थे जबकि 2014 में यह संख्या बढ़कर 34 प्रतिशत हो गई और 2019 में यह आंकड़ा 43 प्रतिशत पर पहुंच गया और 2024 के चुनाव में यह संख्या बढ़कर 46 प्रतिशत हो गई है। एसोसिएशन आफ डैमोक्रेटिक रिफार्म (ए.डी.आर.) की जून, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा लोकसभा के 543 सांसदों में से 251 (46 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 27 सांसद ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी मामले में सजा भी हो चुकी है।

इसी प्रकार ए.डी.आर. की अक्तूबर, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार देश की सभी विधानसभाओं के कुल 4131 विधायकों में से 1861 विधायकों (45 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 1205 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 9 अप्रैल से लेकर 4 मई के मध्य तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं। 2021 में इन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कुल 822 विधायक चुने गए थे और इनमें से 419 (52 प्रतिशत) विधायकों ने चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने की बात कबूल की थी। असम के विधानसभा चुनावों से पहले ए.डी.आर. ने चुनाव मैदान में उतरे 722

एसोसिएशन आफ डैमोक्रेटिक रिफार्म (ए.डी.आर.) की जून, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा लोकसभा के 543 सांसदों में से 251 (46 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 27 सांसद ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी मामले में सजा भी हो चुकी है।

इसी प्रकार ए.डी.आर. की अक्तूबर, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार देश की सभी विधानसभाओं के कुल 4131 विधायकों में से 1861 विधायकों (45 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 1205 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

उम्मीदवारों के हलफनामों का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार 102 (14 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कबूल की है। इनमें से 82 (11 प्रतिशत) उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। असम में कांग्रेस के 99 उम्मीदवारों में से 28, भाजपा के 90 में से 8, आल इंडिया युनाईटड डैमोक्रेटिक फ्रंट के 30 में से 11, असम गण परिषद् के 26 में से 6, रायजोर दल के 13 में से 2, असम जातीय परिषद् के 10 में से 2 तथा सी.पी.आई. मार्क्सवादी के 3 में से 1 उम्मीदवार ने अपने खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। इसी प्रकार पुडुचेरी के 291 उम्मीदवारों में से 66 (23 प्रतिशत) उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने का खुलासा हुआ है। इनमें से 38 उम्मीदवारों (13 प्रतिशत) के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपराधियों को लोकसभा और विधानसभाओं में जाने से रोकने के लिए चुनाव आयोग के पास पर्याप्त कानूनी शक्तियां नहीं हैं। चुनाव आयोग ने हर उम्मीदवार के लिए नामांकन के समय अपने खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की जानकारी शपथपत्र में देना अनिवार्य किया है। साथ ही उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को इन जानकारियों को अखबारों, टी.वी. और डिजिटल माध्यमों पर सार्वजनिक करना होता है, ताकि मतदाता उचित निर्णय ले सकें। राजनीतिक दल जब उम्मीदवारों को टिकट देते हैं तो वह न सिर्फ उम्मीदवार की आर्थिक स्थिति देखते हैं बल्कि यह भी देखा जाता है कि उम्मीदवार की चुनाव जीतने की क्षमता कितनी है। कई उम्मीदवार अपने धन बल और कई उम्मीदवार अपने बाहुबल के चलते संसद और विधानसभाओं में पहुंच जाते हैं। कानून के अनुसार सांसद या विधायक तभी अयोग्य ठहराया जाता है जब उसे किसी मामले में 2 वर्ष से ज्यादा सजा हो जाए। जनता जानकारी के अभाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर देती है। राजनीति से आपराधिक तत्वों को दूर रखने के लिए नेताओं से जुड़े आपराधिक मामलों में तेजी से सुनवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे राजनीतिक दलों की जनता में छवि खराब होती है।

सम्पादकीय...

सुशासन की आवश्यकता

1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में हुए विद्रोह के बाद से, वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद अक्सर हत्याओं, मुठभेड़ों और हिंसा की खबरों के साथ सुर्खियों में बना रहा है। एक समय ऐसा था जब देश के एक चौथाई से अधिक हिस्से-पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जिसे 'रेड कॉरिडोर' कहा जाता था-में नक्सलियों का दबदबा था। जहां सुरक्षा बलों के सदस्यों, नक्सलियों और आम नागरिकों सहित हजारों लोग मारे गए या घायल हुए, वहीं इन क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य लगभग ठप्प हो गया था। नक्सलियों ने अपनी समानांतर सरकार बना ली थी और वे सड़कों के निर्माण या बुनियादी ढांचे के विकास की अनुमति नहीं देते थे, ताकि सरकार और सुरक्षा बलों को दूर रखा जा सके। एक लंबी अवधि तक सरकार इस खतरे से लड़ती रही और नक्सलियों के प्रभाव को मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ तक सीमित करने में सफल रही। इस आंदोलन के खिलाफ एक निर्णायक अभियान 2006 में शुरू हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि माओवादी हिंसा 'आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा' है। हालांकि, वर्तमान सरकार द्वारा इसे बढ़ा चढ़ाया दिया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च, 2026 तक देश को 'नक्सल मुक्त' बनाने की समय सीमा तय की। नक्सली हिंसा से छुटकारा पाने के अपने संकल्प में प्रभावी कदम उठाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को श्रेय दिया जाना चाहिए। अमित शाह ने अपनी निर्धारित समय सीमा से एक दिन पहले देश को 'नक्सल मुक्त' घोषित करते हुए बताया कि पिछले 3 वर्षों में 4,839 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, 706 मारे गए और 2,218 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ''2024 की शुरुआत में माओवादियों की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो में 22 सदस्य थे। आज एक भी नहीं है।'' उन्होंने कहा कि नक्सलवाद 'लगभग खत्म हो चुका है' और माओवादियों के खिलाफ बल प्रयोग का बचाव करते हुए कहा कि जो गोलियां चलाते हैं, उन्हें गोलियों से ही जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किए गए 92 प्रतिशत हथियार पुलिस के शस्त्रागार से लूटे गए थे। जहां हिंसा को समाप्त करने के संकल्प के लिए सरकार को श्रेय दिया जाना चाहिए, वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) के नेतृत्व में अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ संबंधित राज्यों के पुलिस बलों और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ्स) जैसे सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) और सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) ने हिंसा से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां तक कि भारतीय सेना और वायुसेना भी नक्सलियों को बाहर निकालने के लिए कुछ अभियानों में शामिल हुई। लेकिन इसका श्रेय उन अधिकारियों और श्रमिकों को भी जाता है, जो माओवादियों की धमकियों के बावजूद सड़कें बिछाने और बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगे रहे, जिससे अंततः पासा पलट दिया और माओवादियों ने जंगलों में अपना समर्थन खो दिया।

तमिलनाडु में मामला उतना भी सीधा नहीं-विजय ने बनाया चतुष्कोणीय मुकाबला

आर राजगोपालन

अन्नाद्रमुक, विजय के टीवीके जैसी विपक्षी पार्टियों की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है, जबकि एमके स्टालिन की द्रमुक को सबसे ज्यादा सत्ता-विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु में चुनाव का मुख्य मुद्दा नशीले पदार्थ हैं। द्रमुक को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दल अवैध व विदेशी शराब की तस्करी, विश्वविद्यालयों में दुष्कर्म और कानून-व्यवस्था की बदहाल स्थिति जैसे मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। सही सूचना के लिए जनता ने अब सोशल मीडिया और यूट्यूब पर लाइव रिपोर्टिंग देखना शुरू कर दिया है, जो राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ है। द्रमुक और अन्नाद्रमुक की जड़ें तमिलनाडु के हर गांव में फैली हुई हैं, लेकिन भाजपा या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ऐसा नहीं है। एक नई राजनीतिक पार्टी, टीवीके (तमिलगा वेत्री कड़गम-तमिल विजय पार्टी) का गठन हुआ है, जिसे तमिल सिनेमा के 'सुपर हीरो' जोसेफ विजय ने शुरू किया है। इसलिए पहली बार, तमिलनाडु में चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। विजय के राजनीति में आने से राज्य के ईसाई समुदाय को रणनीतिक बढ़ावा मिला है।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है, जहां 23 अप्रैल को मतदान होगा। इस दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला राज्य के करीब छह करोड़ मतदाता करेंगे। लगता है कि इस बार 234 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव के नतीजे एक नया राजनीतिक आश्चर्य और मोड़ लेकर आएंगे। नए जनादेश के तहत सबसे बेहतरीन तालमेल वाले नए चेहरे ही आगामी चार मई को चुनकर अगले पांच वर्षों के लिए विधायक बनेंगे। पिछले 70 वर्षों से, बारी-बारी से या तो द्रमुक ने या फिर अन्नाद्रमुक ने ही राज्य पर राज किया है। अन्नाद्रमुक, विजय के टीवीके जैसी विपक्षी पार्टियों की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है, जबकि एमके स्टालिन की द्रमुक को सबसे ज्यादा सत्ता-विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु में चुनाव का मुख्य मुद्दा नशीले पदार्थ हैं। द्रमुक को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दल अवैध व विदेशी शराब की तस्करी, विश्वविद्यालयों में दुष्कर्म और कानून-व्यवस्था की बदहाल स्थिति जैसे मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। सही सूचना के लिए जनता ने अब सोशल मीडिया और यूट्यूब पर लाइव रिपोर्टिंग देखना शुरू कर दिया है, जो राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ है। द्रमुक और अन्नाद्रमुक की जड़ें तमिलनाडु के हर गांव में फैली हुई हैं, लेकिन भाजपा या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ऐसा नहीं है। एक नई राजनीतिक पार्टी, टीवीके (तमिलगा वेत्री कड़गम-तमिल विजय पार्टी) का गठन हुआ है, जिसे तमिल सिनेमा के 'सुपर हीरो' जोसेफ विजय ने शुरू किया है। इसलिए पहली बार, तमिलनाडु में चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। विजय के राजनीति में आने से राज्य के ईसाई समुदाय को रणनीतिक बढ़ावा मिला है। अल्पसंख्यकों का वोट बैंक एक 'दोधारी तलवार' जैसा है। पहली बार अल्पसंख्यकों के वोट द्रमुक से हटकर टीवीके की तरफ जा सकते हैं। ऐसी उम्मीद है कि टीवीके कुल वोटों में से 20-25 प्रतिशत पर कब्जा कर सकती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि विजय के प्रशंसकों की संख्या बहुत ज्यादा है। तमिलनाडु में भाजपा को मोदी-अमित शाह की जोड़ी से एक बड़ा बढ़ावा मिला है। द्रविड़ प्रदेश में राजग को अन्नाद्रमुक नेता एडप्पाडी पलानीस्वामी से लाभ मिलेगा। जयललिता के जीवनकाल में अन्नाद्रमुक के चुनावी घोषणापत्र में राम मंदिर का जिक्र किया गया था। तमिलनाडु में कमल का चुनावी निशान भी काफी लोकप्रिय है। पिछली विधानसभा में भाजपा के चार विधायक थे। तमिलनाडु में कांग्रेस एक परखी हुई और राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी है। द्रमुक गठबंधन में इसकी मौजूदगी, ज्यादा धर्मनिरपेक्ष वोट हासिल करने के लिए एक नैतिक संबल का काम करती है। दिलचस्प बात यह है कि विजय द्वारा टीवीके की शुरुआत किए जाने और करूर रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद, राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के टीवीके के करीब आने की घटनाओं ने तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। करूर घटना के बाद पिछले छह महीनों में, राहुल गांधी टीवीके के और करीब आने के लिए उत्सुक रहे हैं। लेकिन द्रमुक ने इसे पहले ही भांप लिया। सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से एमके स्टालिन ने कांग्रेस को द्रमुक के नए गठबंधन, धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) से बाहर निकलने से रोक दिया। सीमन 'नाम तमिलर काची' (एनटीके) के नेता हैं। एनटीके लंबे समय से लिट्टे नेता प्रभाकरन की समर्थक रही है और 'तमिल ईलम' के मुद्दे को उठाती रही है। इस चुनाव में वह अकेले ही लड़ रही है। उनके पास आठ प्रतिशत का निश्चित वोट बैंक है, जिसमें वे लोग शामिल हैं, जो 'तमिल राष्ट्रवाद' का समर्थन करते हैं। द्रमुक की चुनावी शैली मुख्य रूप से भाजपा-विरोधी बातों और मोदी व शाह पर की जाने वाली टिप्पणियों पर केंद्रित रहती है। वे 'सनातन धर्म' के खिलाफ नफरत भरे भाषण देते हैं और इसकी तुलना डेंगू व कोरोना जैसी बीमारियों से करते हैं। एमके स्टालिन की रणनीति मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने पर आधारित है। द्रमुक को इस बात का अंदाजा है कि विजय ईसाई वोट अपने पाले में कर लेंगे। मुस्लिम वोटर भी विजय की तरफ झुक सकते हैं। इसके अलावा, कुछ बाहरी कारक भी हैं, जैसे कि चुनाव के लिए पैसे का इंतजाम और देर रात मतदाताओं के बीच नकदी बांटना। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 'लॉटरी किंग' मार्टिन सभी पार्टियों को फंड दे रहे हैं। चुनावी घोषणापत्र अब मजाक का विषय बन गए हैं-फ्रिज, लैपटॉप, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, कुकवेयर, और छात्रों व किशोरों के लिए मुफ्त वाईफाई इंटरनेट की सुविधा देने जैसे वादे किए जा रहे हैं। विजय तो मुफ्त की चीजें देने के मामले में और भी आगे निकल गए हैं। इसके अलावा, अन्नाद्रमुक से निकाले गए नेताओं पर द्रमुक दांव लगा रही है और उन्हें उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। पिछले चुनावों में, जब मुकाबला मुख्य रूप से द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच था, तब जीत हासिल करने में ईसाई और मुस्लिम समुदायों के समर्थन ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन टीवीके के चुनावी मैदान में प्रवेश और जोसेफ विजय के 'ईसाई' होने की पहचान की वजह से, अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों का एक हिस्सा उनकी तरफ जाने की उम्मीद है। चूंकि, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मुख्य रूप से द्रमुक और टीवीके में से किसी एक को चुनने वाले हैं, ऐसे में हिंदू वोट (जिनमें कोनार, मुकुलाथोर, मुथरैयर और अनुसूचित जातियां शामिल हैं) निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। सभी पार्टियों के चुनावी अभियानों और तमिलनाडु के मिजाज को देखते हुए कहा जा सकता है कि राज्य में मुकाबला कड़ा होगा। नशीले पदार्थ और अवैध शराब मुख्य चर्चा का विषय होंगे। अगले दो हफ्तों तक जोशीले और भड़काऊ भाषण, नुक्कड़ सभाएं और रोड शो देखने को मिलेंगे। चतुष्कोणीय मुकाबले में जीत का अंतर एक हजार मतों से भी कम रहने की संभावना है। कई जनमत सर्वेक्षण मिश्रित नतीजों का अनुमान लगा रहे हैं। तमिलनाडु में सत्ता-विरोधी लहर के चलते, कुछ लोग 'त्रिशंकु विधानसभा' की भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि, तमिलनाडु में स्वतंत्र और हिंसा-मुक्त चुनाव देखने को मिलेगा, जो लोकतंत्र की खासियत है।

बुजुर्गों के भरण-पोषण के लिये एक सराहनीय पहल

भारतीय संस्कृति में माता-पिता को देवतुल्य माना गया है- मातृदेवो भव, पितृदेवो भव केवल शास्त्रों की पंक्ति नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक संरचना की आत्मा रही है। इसलिए यह किसी भी सभ्य समाज के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है कि जन्म देने और पालन-पोषण करने वाले माता-पिता को जीवन की सांझ में उपेक्षा, अपमान और आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़े, और उन्हें अपने ही बच्चों से गुजारा भत्ता पाने के लिए कानून और प्रशासन का सहारा लेना पड़े। दुर्भाग्य से यह आज के समय की कठोर वास्तविकता बनती जा रही है। बुढ़ापा अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की क्षमताएं कम होने लगती हैं, बीमारियां बढ़ने लगती हैं और आय के स्रोत लगभग समाप्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्ति के समय जो थोड़ी बहुत जमा-पूंजी होती है, वह बच्चों की पढ़ाई, शादी-ब्याह और मकान बनाने में खर्च हो जाती है। सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन मिल भी जाती है, लेकिन निजी क्षेत्र या छोटे व्यवसाय से जुड़े लोगों की स्थिति अधिक कठिन हो जाती है। ऐसे समय में यदि बच्चे ही माता-पिता की देखभाल न करें तो यह केवल पारिवारिक विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए तेलंगाना विधानसभा द्वारा पारित «तेलंगाना कर्मचारी जवाबदेही और माता-पिता सहायता निगरानी विधेयक 2026 एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल के रूप में सामने आया है। इस विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि बच्चे अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते, तो उनके वेतन से एक निश्चित राशि काटकर माता-पिता को दी जाए। यह कानून सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों, सांसदों, विधायकों और स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों पर भी लागू होगा। इस प्रकार यह कानून केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी को कानूनी रूप देने का प्रयास है। हालांकि भारत में पहले से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 मौजूद है, लेकिन तेलंगाना का यह नया विधेयक अधिक व्यापक, सक्रियात्मक और प्रभावी माना जा रहा है। इसमें प्रावधान है कि यदि बच्चे माता-पिता की देखभाल नहीं करते, तो शिकायत मिलने पर उनके वेतन से पंद्रह प्रतिशत या दस हजार रुपये (जो भी कम हो) काटकर माता-पिता के खाते में जमा किए जाएंगे। शिकायत का निस्तारण जिला कलेक्टर द्वारा साठ दिनों के भीतर किया जाएगा और इसके लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन भी किया जाएगा। इस कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें केवल जैविक माता-पिता ही नहीं, बल्कि सौतेले माता-पिता भी शिकायत कर सकते हैं। यह कानून इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भारतीय परिवार व्यवस्था तेजी से बदल रही है। संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में बदल चुके हैं और अब तो एक व्यक्ति परिवार की अवधारणा भी विकसित हो रही है। करियर की दौड़, आर्थिक दबाव, शहरी जीवनशैली, सुविधावाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बढ़ती भावना ने परिवार की पारंपरिक संरचना को कमजोर किया है। कई बार माता-पिता को घर से निकालकर वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है, और यदि घर में रख भी लिया जाए तो उन्हें उपेक्षा, तिरस्कार और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। उनकी दवाइयों, भोजन और देखभाल तक में लापरवाही बरती जाती है। ऐसी परिस्थितियों में यह प्रश्न उठता है कि क्या माता-पिता की सेवा केवल संस्कारों से सुनिश्चित की जा सकती है या इसके लिए कानून की भी आवश्यकता है? आदर्श स्थिति में तो संस्कार ही पर्याप्त होने चाहिए। भारतीय इतिहास और परंपरा में माता-पिता की सेवा के अनेक प्रेरक उदाहरण मिलते हैं। श्रवण कुमार का उदाहरण तो भारतीय संस्कृति में आदर्श पुत्र का प्रतीक बन चुका है, जिसने अपने अंधे माता-पिता को कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाई। इसी प्रकार भगवान श्रीराम ने पिता के वचन को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर वनवास स्वीकार किया। यह केवल धार्मिक कथाएं नहीं, बल्कि भारतीय समाज की नैतिक संरचना के आदर्श हैं। इतिहास में छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे अनेक व्यक्तित्वों के जीवन में भी माता-पिता के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान देखने को मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि माता-पिता के प्रति सम्मान और सेवा भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा रही है। लेकिन आज जब संस्कार कमजोर हो रहे हैं, तब समाज को कानून का सहारा लेना पड़ रहा है।

लेकिन इस पूरे विषय को केवल एकतरफा दृष्टि से देखना भी उचित नहीं होगा। यह भी एक सच्चाई है कि कई बार माता-पिता भी बच्चों के प्रति अत्यधिक अनुशासन, नियंत्रण और अपेक्षाओं का दबाव बनाते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे हमेशा उनकी इच्छाओं के अनुसार ही जीवन जिएं, अपने निर्णय स्वयं न लें, विवाह, करियर, जीवनशैली हर चीज में माता-पिता की इच्छा सर्वोपरि रहे। कई बार माता-पिता बच्चों की निजी जिंदगी में अत्यधिक हस्तक्षेप करते हैं, जिससे परिवार में तनाव उत्पन्न होता है। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों और माता-पिता के बीच दूरी बढ़ जाती है और पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। इसलिए समस्या का समाधान केवल कानून नहीं है, बल्कि परिवार के भीतर संतुलन, संवाद और समझ भी उतनी ही आवश्यक है। बच्चों को यह समझना चाहिए कि माता-पिता ने उनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, इसलिए बुढ़ापे में उनकी सेवा और सम्मान उनका नैतिक कर्तव्य है। वहीं माता-पिता को भी यह समझना चाहिए कि समय बदल गया है, नई पीढ़ी की जीवनशैली और सोच अलग है, इसलिए उन्हें बच्चों को समझने और उन्हें स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है। वास्तव में परिवार एक संस्था है, जो प्रेम, त्याग, सम्मान और संवाद पर चलती है, न कि केवल अधिकार और अनुशासन पर। जहां केवल अधिकार होंगे, वहां टकराव होगा; जहां केवल त्याग होगा, वहां असंतुलन होगा; लेकिन जहां प्रेम और संतुलन होगा, वहां परिवार मजबूत होगा। तेलंगाना का यह कानून एक महत्वपूर्ण पहल है, लेकिन यह अंतिम समाधान नहीं है। कानून बच्चों को माता-पिता का भरण-पोषण करने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन वह प्रेम, सम्मान और संवेदना पैदा नहीं कर सकता। इसके लिए समाज में नैतिक शिक्षा, पारिवारिक संस्कार और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। स्कूलों में, सामाजिक संस्थाओं में और धार्मिक संगठनों में परिवार और बुजुर्गों के सम्मान की शिक्षा दी जानी चाहिए। आज «नया भारत» और «विकसित भारत» की बात की जा रही है, लेकिन केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं है। यदि समाज में बुजुर्ग असुरक्षित, उपेक्षित और अपमानित होंगे, तो विकास अधूरा रहेगा। वास्तविक विकास वही है जिसमें समाज का हर वर्ग-बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकें। अतः आवश्यक है कि हम तीन स्तरों पर कार्य करें-पहला, सरकार और कानून बुजुर्गों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। दूसरा, समाज में माता-पिता के सम्मान और सेवा के संस्कार विकसित किए जाएं। तीसरा, परिवार के भीतर माता-पिता और बच्चों के बीच संतुलित और संवादपूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं। यदि ये तीनों स्तर मजबूत हो जाएं, तो न केवल बुजुर्गों का जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक होगा, बल्कि परिवार संस्था भी मजबूत होगी और समाज में मानवीय संवेदनाएं जीवित रहेंगी। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि माता-पिता केवल परिवार का हिस्सा नहीं होते, वे परिवार की जड़ होते हैं। यदि जड़ कमजोर होगी, तो वृक्ष भी कमजोर होगा। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान और सुरक्षा केवल एक पारिवारिक या कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि समाज की नैतिकता और सभ्यता की परीक्षा है। जो समाज अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, वह कभी महान नहीं बन सकता।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पेन्टागन एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं। विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/38882)

बैंक ऑफ बड़ौदा की दरियागंज में नई शाखा का उद्घाटन

नई दिल्ली (साहिल गौड़)बैंक ऑफ बड़ौदा ने दरियागंज में अपनी नई शाखा का उद्घाटन किया। इस पहल के साथ बैंक ने राष्ट्रीय राजधानी में अपनी उपस्थिति को और सुदृढ़ करते हुए स्थानीय निवासियों एवं व्यापारियों के लिए बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया है।

शाखा का उद्घाटन श्री एम.वी.एस. सुधाकर, महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख, नई दिल्ली क्षेत्र, के कर-कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में श्री सुधाकर ने बैंक की ग्राहक-केंद्रित सेवाओं के विस्तार तथा वित्तीय समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि नई शाखा में आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं, खुदरा बैंकिंग, डिजिटल सेवाएं तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्यक्रम में श्री अजीत सिंह यादव, शाखा प्रमुख, दरियागंज शाखा; सुश्री प्रग्या बिसेन, उप क्षेत्रीय प्रमुख, पूर्वी दिल्ली क्षेत्र; श्री सनी चावला, क्षेत्रीय प्रमुख, पूर्वी दिल्ली क्षेत्र; तथा श्री एम.एस. चौहान, पूर्व प्रबंधक भी उपस्थित रहे, जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। 11बी, नेताजी सुभाष मार्ग स्थित यह नई शाखा क्षेत्र के व्यावसायिक एवं आवासीय इलाकों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगी।

इस नई शाखा के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने नई दिल्ली में अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए एक विश्वसनीय बैंकिंग साझेदार के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत किया है।

महावीर मंदिर में भव्य भंडारा, हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

पडरौना, कुशीनगर।

महावीरी मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव एवं श्री रामचरितमानस पाठ के पावन समापन के उपरांत भव्य भंडारे का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल की उपस्थिति में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया।

भंडारे में नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मंदिर परिसर में भक्ति संगीत, जय श्री राम एवं जय हनुमान के जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा, जिससे क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत नजर आया। इस अवसर पर विनय जायसवाल ने कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों से समाज में आपसी सौहार्द, एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। उन्होंने भगवान श्रीराम और हनुमान के आदर्शों को अपनाकर समाज को सशक्त बनाने की बात कही। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल सहित पुजारी गौरी शंकर लाटा, दीपक त्रिपाठी, विवेक अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, जयप्रकाश वर्मा, वासु चौरसिया, पिंकू वर्मा, दीपक वर्मा, श्याम वर्मा, आदित्य गुप्ता, विराट त्रिपाठी, आलोक गुप्ता, राजेश वर्मा, कपिल चौबे, विवेक उपाध्याय, जयप्रकाश चौरसिया, सुमित गुप्ता, मनीष गुप्ता, अक्षय वर्मा, संजय गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, शंभू चौरसिया, बंटी गुप्ता, हर्ष मोदनवाल, विकास अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

सभी ने मिलकर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया, जिससे कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

60 फीट ऊंचा झूला उखड़कर गिरा, 30 घायल; मेले में मचा हड़कंप

खड्डा, कुशीनगर।

खड्डा थाना क्षेत्र के भैसहा मेले में बुधवार देर रात बड़ा हादसा हो गया, जब करीब 60 फीट ऊंचा झूला अचानक उखड़कर गिर गया। हादसे में करीब 30 लोग घायल हो गए, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दो बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 10 से अधिक घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना रात करीब 11:30 बजे की है। झूले पर उस समय लगभग 80 लोग सवार थे। झूला दो बार घूमने के बाद चरमराने लगा और लोगों ने ऑपरेटर को आवाज लगाई, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। कुछ ही देर बाद तेज आवाज के साथ झूला उखड़कर जमीन पर गिर गया, जिससे उसमें बैठे लोग नीचे आ गिरे और कई लोग उसके नीचे दब गए। हादसे के बाद मेले में अफरा-तफरी और

चीख-पुकार मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद झूले के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।

छह एंबुलेंस की मदद से घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भेजा गया। घायल लालू गुप्ता ने बताया कि झूले पर बैठते समय ही अजीब आवाज आ रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दो चक्कर के बाद झूला अचानक टूटकर गिर गया। हादसे में झूले के आसपास खड़े लोग और पास की कुछ दुकानें भी चपेट में आ गईं। प्राथमिक जांच में झूले के बेस के कमजोर होने की बात सामने आ रही है। आशंका है कि झूले को जमीन में ठीक से नहीं गाड़ा गया था, जिससे वह भार सहन नहीं कर सका। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लापरवाही के बिंदुओं की पड़ताल की जा रही है। भैसहा मेला नारायणी नदी के तट पर स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर के पास प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है, जहां पूर्वांचल के साथ-साथ नेपाल और बिहार से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हादसे के बाद मेले की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं।

सेमीफाइनल में बसंतपुर व गोबरही की धमाकेदार जीत, फाइनल में भिड़ंत तय

राजापाकड़ धाम, कुशीनगर। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यज्ञ समिति राजापाकड़ धाम की क्रिकेट समिति के तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय श्री अंजनीसुत रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन खेले गए दोनों सेमीफाइनल मुकाबले एकतरफा रहे। अरुण इलेवन बसंतपुर और डब्ल्यू इलेवन गोबरही ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। पहले सेमीफाइनल में अरुण इलेवन बसंतपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए दीपक इलेवन बभनौली को छह ओवर में पांच विकेट पर महज 26 रन पर रोक दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए बसंतपुर की टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पांचवें ओवर में ही दो विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। कप्तान अरुण ने सात गेंदों में 12 रन की तेज पारी खेली और गेंदबाजी में भी एक विकेट लेकर शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया।

शिक्षा चौपाल एवं विद्यालय वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन

जौनपुर।

जनपद के सिरकोनी विकासखंड अंतर्गत कम्पोजिट विद्यालय सेहमलपुर में शिक्षा चौपाल एवं विद्यालय वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन बड़े ही उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निपुण भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ शैक्षिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया एवं विशिष्ट अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने नवीन नामांकित बच्चों का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा उन्हें कॉपी-पेंसिल वितरित कर प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल ने अभिभावकों से अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराने की अपील की। साथ ही कार्यक्रम के दौरान 20 नए बच्चों का नामांकन भी कराया गया। कार्यक्रम की विशेष आकर्षण आरुषि यादव एवं आयुषी यादव

द्वारा बनाई गई कलाकृति रही, जिसे मुख्य विकास अधिकारी को भेंट किया गया। कलाकृति से प्रभावित होकर उन्होंने दोनों छात्राओं एवं उनकी माता को शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विद्यालय परिवार द्वारा आगंतुक अभिभावकों एवं ग्रामवासियों का गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी अमरेश कुमार सिंह सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और गुणवत्ता सुधार पर विशेष बल दिया। अंत में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक इरफान खान ने सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और अभिभावकों की सहभागिता भी सशक्त होती है। कार्यक्रम में शिक्षकगण, अभिभावक एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समूचा आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली नहर में पलटी, महिला की मौत; दो दर्जन से अधिक घायल

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। चैत्र रामनवमी के अवसर पर स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली बुधवार रात अनियंत्रित होकर बड़ी गंडक नहर में पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार महाराजगंज जिले के माहनखोर उर्फ बड़हरा (थाना घुघली) से करीब 50 श्रद्धालु नारायणी नदी के भैंसहा घाट पर स्नान मेले में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान खड्डा थाना क्षेत्र के सिसवा गोपाल (सिंसई) रेगुलेटर के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया और ट्रॉली नहर में जा गिरी। बताया जा रहा है कि नहर में उस समय पानी नहीं था, लेकिन लगभग 30 फीट गहराई होने के कारण ट्रॉली के नीचे कई लोग दब गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रॉली में 25-30 महिलाएं, करीब 10 बच्चे और 10 पुरुष सवार थे। पीछे बैठे कुछ लोग कूदकर बच निकले, लेकिन अधिकांश घायल हो

गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। ट्रैक्टर की मदद से ट्रॉली को बाहर निकाला गया और उसके नीचे दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अंधेरा होने के बावजूद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद विधायक विवेकानंद पांडेय अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार एवं हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण चालक का नियंत्रण खोना बताया जा रहा है।

प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, बोलीं- पीएम मोदी की बी-टीम हैं केरला सीएम विजयन

केरल। तिरुवनंतपुरम् में एक जनसभा के दौरान, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के लोगों की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत की सच्ची भावना का प्रतीक बताया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता और करुणा की राज्य की परंपराओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह नारायण गुरुजी जैसे क्रांतिकारी विचारकों की भूमि है। वे महात्मा गांधी जी के महान प्रेरणास्रोतों में से एक थे और कई मायनों में, आप आज भी उनकी परंपराओं को जी रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अच्छी शिक्षा, समानता, एक-दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा की परंपराएं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि केरल की भावना ही भारत की सच्ची भावना है। एएनआई से बात करते हुए, गांधी ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति की आलोचना की और कहा कि उनकी गैरमौजूदगी से संकेत मिलता है कि वे इस चर्चा को महत्वपूर्ण नहीं मानते। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा थी जो होनी ही थी, लेकिन उन्होंने वहां न आने का विकल्प चुना। वे स्पष्ट रूप से इसे उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते। गांधी लोकसभा में वायनाड का प्रतिनिधित्व करती हैं। अटिंगल संसदीय क्षेत्र का हिस्सा तिरुवनंतपुरम् पिछले तीन विधानसभा चुनावों में

वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) के पास रहा है। आगामी चुनाव में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) की उम्मीदवार राम्या हरिदास हैं, जो अलाथुर से पूर्व लोकसभा सांसद (2019-2024) रह चुकी हैं। हरिदास का मुकाबला सीपीआई के मनोज बी एडमाना और भाजपा के बी एस अनूप से होगा। अनूप ने इससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम् से यूडीएफ के टिकट पर चुनाव लड़ा था। अपने भाषण में गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ दोनों की जनता की जरूरतों को अनदेखी करने के लिए आलोचना की। उन्होंने मोदी पर भारत की संप्रभुता से समझौता करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियां हमारी जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने इसके बजाय इजरायल और अमेरिका के सामने झुकना चुना है। हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी ऊर्जा सुरक्षा अमेरिकियों को सौंप दी है और हमारा भविष्य उनके हाथों में दे दिया है। अब वे हमें बताते हैं कि हम किससे और कब खरीद सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला करते हुए उन्हें कायर कहा और आरोप लगाया कि मोदी कायर हैं। उनमें भारत के लिए खड़े होने का साहस नहीं है। उनके फैसलों की कीमत जनता को हर दिन चुकानी पड़ रही है। हम इसलिए कीमत चुका रहे हैं क्योंकि उनका नाम एपस्टीन की कुछ फाइलों में है। गांधी ने राज्य सरकार पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि केरल के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बी-टीम की तरह काम कर रहे हैं। केंद्र ने किसी भी वामपंथी नेता पर हमला क्यों नहीं किया सबरीमाला मंदिर में बड़ी चोरी होने पर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा।

होर्मुज पर ब्रिटेन में 60+ देशों की बड़ी बैठक- भारत से शामिल हुए मिसरी; कहा- हमने नाविक खोए, जल्द रुके तनाव

नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की पहल पर करीब 60 से अधिक देशों के विदेश मंत्रियों ने ऑनलाइन तरीके से होर्मुज संकट पर गुरुवार को चर्चा की। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विक्रम मिसरी ने किया और अध्यक्षता ब्रिटेन के विदेश मंत्री यवेट कूपर ने की।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य की आंशिक नाकाबंदी के मद्देनजर सुरक्षित समुद्री परिवहन सुनिश्चित करना था।

संकट का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर

मिसरी ने वर्चुअल माध्यम से चर्चा में भाग लेते हुए क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन मार्गों की सुरक्षा पर नई दिल्ली का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने दुनियाभर के देशों के सामने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही हर देश का हक है। इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। विदेश सचिव ने चिंता जताई कि इस पूरे संकट का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है। ब्रिटेन की ओर से बुलाई गई बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारत ने दुनिया के सामने रखी, वह थी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। विदेश सचिव ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों में भारत इकलौता ऐसा देश है, जिसने अपने जांबाज नाविकों को खोया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल और अधिक युद्ध नहीं है। अगर दुनिया को इस संकट से बाहर निकलना है, तो सभी पक्षों को तुरंत हथियारों को शांत कर बातचीत की मेज पर लौटना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, भारत का पक्ष स्पष्ट है। हम स्वतंत्र और खुले वाणिज्यिक परिवहन और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्री सुरक्षा के पक्षधर हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।

जायसवाल ने बताया कि ब्रिटेन ने भारत समेत कई देशों को होर्मुज जलडमरूमध्य पर वार्ता के लिए आमंत्रित किया था और मिसरी ने इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा, हम ईरान और अन्य देशों के संपर्क में हैं ताकि एलपीजी और एलएनजी सहित अन्य उत्पादों को ले जाने वाले हमारे जहाजों के लिए निर्बाध और सुरक्षित पारगमन सुनिश्चित कर सकें। पिछले कुछ दिनों में हुई इन वार्ताओं के कारण भारतीय ध्वज वाले छह जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित पार करने में सक्षम हुए हैं। हम इस मामले पर संबंधित पक्षों के साथ लगातार संपर्क में हैं। सरकार पश्चिम एशिया संघर्ष से संबंधित सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रही है।

होर्मुज से जहाजरानी सेवाएं फिर शुरू करना आसान नहीं - स्टार्मर

वहीं, बैठक के बारे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा, होर्मुज से जहाजरानी सेवाओं को फिर से शुरू करना आसान नहीं होगा और इसके लिए समुद्री उद्योग साझेदारी के अलावा सैन्य शक्ति और राजनयिक गतिविधियों का एक संयुक्त मोर्चा आवश्यक होगा। स्टार्मर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस अपील को स्पष्ट नकार चुके हैं कि ब्रिटेन व यूरोप के अन्य देशों को होर्मुज खुलवाने के लिए सेना का इस्तेमाल करना चाहिए।

जब तक लड़ाई जारी रहेगी, होर्मुज मार्ग अस्थिर रहेगा- चीन

इस बीच, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने चेतावनी दी कि होर्मुज जलडमरूमध्य से आवागमन का मुद्दा ईरान युद्ध का ही परिणाम है और जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जलडमरूमध्य स्थिर नहीं रहेगा। वांग यी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से फोन पर बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां की, जिसमें उन्होंने शीघ्र युद्धविराम का भी आह्वान किया।

ईरान-यूएस जंग पर ओवैसी की पीएम मोदी से अपील, सिर्फ आप ही रुकवा सकते हैं ये युद्ध

नई दिल्ली । एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2 अप्रैल को ईरान के साथ संघर्ष के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए, ट्रंप की सैन्य आक्रमण की योजनाओं पर चिंता व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया। हैदराबाद के सांसद ने इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों को हो रही कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। ओवैसी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अब वहां सैन्य आक्रमण करेंगे। वाणिज्यिक गैस प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। अब भारत को और भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह बहुत चिंताजनक है क्योंकि कई भारतीय नागरिक जीसीसी देशों में काम करते हैं। हमें अब भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) युद्ध समाप्त करने की वकालत करेंगे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। ओवैसी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की ओर बढ़ते कदम की भी आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक और भारत के संविधान के सिद्धांतों के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। प्रस्तावना में विचार की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात कही गई है। यूसीसी के नाम पर हिंदू संहिता विधेयक थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत और असंवैधानिक है। यह घटना फरवरी के अंत में ईरान के साथ शुरू हुई हालिया शत्रुता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ अमेरिकी सेना की निर्णायक कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा था कि अभियान के मुख्य उद्देश्य पूरे होने के करीब हैं।

ईरान पर जीत हासिल की- ट्रम्प

उनकी सेना हमारे कंट्रोल में, समझौता नहीं किया तो पाषाण युग में पहुंचा देंगे

वॉशिंगटन डीसी ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिली है।

साथ ही चेतावनी दी कि अमेरिका 2-3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। ट्रम्प ने आगे कहा कि ईरान की मिसाइल-ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो गई है। सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है। इस सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है। ट्रम्प ने यह भी चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ, तो अमेरिका, ईरान को स्टोन एज, यानी पाषाण काल में भेज देगा। हालांकि उन्होंने यह दावा भी किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर है। ट्रम्प ने 19 मिनट का भाषण दिया। इसमें कोई नया ऐलान नहीं किया। वही बातें दुहराईं जो पिछले कुछ समय से कहते रहे हैं। उन्होंने युद्ध की लागत और इसके लंबा खिंचने से चिंतित अमेरिकियों से कहा कि वे इस संघर्ष को सही नजरिए से देखें। उन्होंने इराक (8 साल) और वियतनाम (19 साल) जैसे पिछले अमेरिकी युद्धों का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान जंग तो अभी दूसरे महीने में ही पहुंची है। उन्होंने यह भी माना कि लोगों को आर्थिक परेशानी हो रही है, लेकिन कहा कि यह युद्ध जरूरी है।

उन्होंने कहा, यह आपके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में निवेश है। ट्रम्प ने ईरान से युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की मांग की, जबकि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि उन्हें समझौते की जरूरत नहीं है। उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट संकट को लेकर कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरे देशों को लेनी चाहिए। हालांकि, एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि होर्मुज खोले बिना कोई समझौता नहीं होगा।

मालदा की घटना पर भड़कीं ममता- बोलीं- मेरी सारी शक्तियां छीन लीं, चुनाव आयोग और भाजपा पर भी साधा निशाना

मुर्शिदाबाद । पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने मालदा जिले में मतदाता सूची में सुधार के काम में लगे न्यायिक अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों द्वारा घेरे जाने की घटना पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग अपने अधिकारियों की रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम रहा। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के सागरदिघी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। उन्होंने कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात के लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया।

चुनाव आयोग कानून-व्यवस्था संभालने में विफल

ममता बनर्जी ने कहा कि मालदा में सात न्यायिक अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों तक घेरे रखा। इन अधिकारियों को सुरक्षा बलों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। यह अधिकारी मतदाता सूची से नाम काटे जाने के विरोध में हो रहे प्रदर्शन का सामना कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद से आयोग ने प्रशासन और पुलिस के सभी बड़े अधिकारियों को अपनी पसंद से तैनात किया है। इसके बावजूद वह सुरक्षा देने में विफल साबित हो रहा है। रैली में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक जैसे बड़े अधिकारियों को चुनाव आयोग ने हटा दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं और प्रशासन अब पूरी तरह आयोग के हाथ में है। ममता के मुताबिक, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा चुनाव आयोग पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में पूरी तरह असमर्थ है।

बीजेपी पर लगाया चुनाव रद्द कराने की साजिश का आरोप

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी बंगाल में विधानसभा चुनाव रद्द कराना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की असली योजना राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा में सांप्रदायिक लोग शामिल हैं और कुछ ऐसे ही लोग अब आपके बीच भी घुस आए हैं। उन्होंने जनता को आगाह किया कि राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने किसी का नाम लिए बिना हैदराबाद की पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैदराबाद से भाजपा के पैसे लेकर बंगाल आए हैं। उनका एकमात्र मकसद मुस्लिम वोटों को बांटना है ताकि इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सके। मुख्यमंत्री ने रैली में मौजूद लोगों से अपील की कि वे ऐसी ताकतों से सावधान रहें और एकजुट होकर मतदान करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य की शांति और एकता को बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

घुसपैठ के कारण बंगाल का अस्तित्व खतरे में- शाह

शाह बोले- 15 दिन बंगाल में रहूंगा-ममता को घर में हराना है, टीएमसी को खाड़ी में फेंक दो; शाह को काले झंडे दिखाए

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में रोड शो किया। उन्होंने कहा- मैं अगले 15 दिन बंगाल में रहने वाला हूं। इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने और उसे बंगाल की खाड़ी में फेंकने के लिए हर किसी को बिना किसी डर के वोट देना चाहिए। कोई भी गुंडा बंगाल के मतदाताओं को नहीं रोक सकता। शाह का काफिला जब कालीघाट पहुंचा, जहां से ममता का घर कुछ ही दूर है वहां पर टीएमसी कार्यकर्ता ने काफिले के सामने जय बांग्ला और ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाए। सिर पर काला कपड़ा बांधे लोगों ने अमित शाह गो बैक के नारे लगाए और काले झंडे भी दिखाए। इसके बाद टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प होने लगी। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की और भीड़ पर कंट्रोल किया। इससे पहले शाह ने कोलकाता में रैली में कहा- सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि सिर्फ नंदीग्राम में ही नहीं बल्कि हमें ममता को उनके घर में भी हराना होगा। दरअसल, सीएम ममता पश्चिम बंगाल की भवानीपुर और नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ सुवेंदु अधिकारी को दोनों सीट से मैदान में उतारा है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल किया।

असम विधान सभा चुनाव में कांग्रेस ने झोंकी ताकत

जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, महिलाओं को 50 हजार देने का ऐलान!

असम । असम विधानसभा की 126 सदस्यीय सीट के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। इस दौरान कांग्रेस का आज घोषणापत्र जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी पांच गारंटी पहले ही जारी हो चुकी हैं। असम में हमने महिलाओं के खातों में 50 हजार रुपये का ऋण डालने की बात की है, वृद्धावस्था पेंशन को 1250 रुपये करने की बात की है, एक मंत्रालय बनाने की बात की जा रही है। हम जमीन के पट्टे की बात कर रहे हैं जिसमें 10 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा और हम जुबीन गर्ग के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि असम में भ्रष्ट सरकार है जिसने पिछले 5 से 10 सालों में केवल जुमले दिए हैं और कोई भी काम नहीं किया है। जरूरी है कि इस जुमलेबाज सरकार की कलई खोली जाए। आप को बता दें कि असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। यहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी वापसी की राह तलाश रही है।

असम कांग्रेस की कमान गौरव गोगोई के हाथों में है। हालांकि 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए मतदान एक चरण में 9 अप्रैल को होगा जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी। फिलहाल 4 मई को ही ये साफ होगा कि सत्ता में भाजपा कब्जा पर रहेगी या फिर कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी।

पश्चिम बंगाल में 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर बंधक

सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- हमें पता है उपद्रवी कौन

वोटर लिस्ट से नाम कटने पर लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन

कोलकाता । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एसआईआर से जुड़े 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाए जाने की घटना पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा- उन्हें नौ घंटे बंधक बनाकर रखा। खाना-पानी तक नहीं मिला। यह घटना सोची-समझी और भड़काऊ लगती है। हमें पता है उपद्रवी कौन है, इनका मकसद न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है।

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था ढह गई है। बेंच ने राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों से उनकी निष्क्रियता पर जवाब मांगा। दरअसल, 7 न्यायिक अधिकारी बुधवार को मालदा के बीडीओ ऑफिस पहुंचे थे। इनमें तीन महिलाएं थीं। तभी वोटर लिस्ट में नाम कटने के विरोध में हजारों लोगों ने ऑफिस को घेर लिया। मालदा में लगातार दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गुरुवार को नारायणपुर स्थित बीएसएफ कैंप के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने नेशनल हाईवे-12 को जाम कर दिया। सड़क पर टायरों में आग लगा दी गई।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, अराजकता फैलाने का लगाया आरोप

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल से एक ऐसी हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिसने देश की न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, मालदा जिले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मतदाता सूची के सुधार का काम करने पहुंचे सात न्यायिक अधिकारी को एक उग्र भीड़ ने करीब 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बंधक बनाए गए अधिकारियों में तीन महिला भी शामिल थीं। इस घटना के बाद देश की सियासत गरमा गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। भाटिया ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ही कभी ऐसी स्थिति देखी गई हो, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पश्चिम बंगाल में चल रही कानूनी प्रक्रिया को इस तरह से रोका गया हो। उन्होंने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ममता बनर्जी की सरकार में कानून-व्यवस्था की हालत इतनी बिगड़ जाएगी।

हिंसा और टीएमसी एक-दूसरे के पर्याय- स्मृति ईरानी

भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भ्रष्टाचार और टीएमसी, हिंसा और टीएमसी एक-दूसरे के पर्याय बन गए हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने यह संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार-मुक्त पश्चिम बंगाल बनाने के लिए, डर के माहौल को खत्म करने के लिए, महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनाना जरूरी हो गया है।

अब तक सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई- रवि किशन

वहीं, सांसद रवि किशन ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। पिछले दो चुनावों से, जब भी मैं प्रचार के लिए बाहर जाता था, तो मुझे वहां सुरक्षा नहीं दी जाती थी। यह एक गंभीर समस्या थी। भाजपा सदस्यों के साथ ऐसा होता रहा है। अब तक वहां सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। दीदी चुनाव हार रही हैं और भाजपा सरकार बना रही है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की जांच और सुधार के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया चलाने का आदेश दिया था। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस काम की जिम्मेदारी न्यायिक अधिकारियों को सौंपी गई थी। 1 अप्रैल को मालदा जिले के कालियाचक-II ब्लॉक में ये अधिकारी अपना काम कर रहे थे। इसी दौरान दोपहर करीब दो से तीन बजे के बीच भीड़ ने दफ्तर को घेर लिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने अधिकारियों को बंधक बना लिया। हद तो तब हो गई जब इन अधिकारियों को कई घंटों तक पानी और खाना तक नसीब नहीं हुआ। उपद्रवियों ने नेशनल हाईवे-12 को भी जाम कर दिया। देर रात करीब 1 बजे भारी पुलिस बलों ने बड़ी मुश्किल से न्यायिक अधिकारियों को वहां से सुरक्षित निकाला। इस दौरान अधिकारियों को ले जा रही गाड़ियों पर पथराव की भी खबरें आईं।